

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 50/21

GCMS NO 2021/81



1. जुआन सिंह पुत्र भगवती
2. गवान सिंह पुत्र भगवती
3. बिहादुर पुत्र भगवती
4. शिमला पत्नि बनीसिंह
5. यादराम पुत्र बनीसिंह
6. मीठया पुत्र बनीसिंह
7. रेखसिंह पुत्र बनीसिंह
8. प्रेम सिंह पुत्र बनी सिंह
9. विनीता पुत्री बनी सिंह
10. देवी सिंह पुत्र राम सिंह
11. रामधन पुत्र बण्डा सभी जातियान गुर्जर निवासीयान सौरया तहसील करौली जिला करौली अपीलांट

बनाम

1. ठाकुर जी महाराज मनोहर जी, वाके ग्राम सौरया तहसील करौली जरिये पुजारी प्रबंधक नेक्सट फ्रेंड रमेशदास चेला तुलसीदास जाति ब्राह्मण निवासी कमनपुर सौरया तहसील करौली जिला करौली हाल आबाद ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर जिला करौली
2. रामखिलाडी पुत्र रामहेत जाति कुम्हार निवासी कमनपुर (सौरया) तहसील करौली जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 58/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.3.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर शर्मा
अभिभाषक रेस्पो0 1 श्री लियाकत अली

दिनांक 15.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.3.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार स हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा घोषणा खातेदारी एवं दखल व रथाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी ठाकुरजी ग्राम सौरया तहसील करौली मे विराजमान है जो शास्वत नाबालिंग है। उनकी सेवा पूजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर




जमीन जायदाद की व्यवस्था वादी द्वारा की जाती है। यह दावा ठाकुरजी से कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नहीं है। आराजी खसरा न0 202,203,204 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा ग्राम सौरया पटवार हल्का खबनगर मे वादी के खातेदारी व कब्जे की स्थित है। काश्तकारी अधिनियम कॉलम होने के दिन सम्वत 2012 मे विवादित आराजी वादी ठाकुरजी के कब्जे काश्त की भी सेटलमेंट विभाग ने गलत तरीके से सम्वत 2015 मे वादी के नाम का इन्द्राज खातेदारी के कॉलम मे से हटा दिया जबकि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है मात्र वारिसी इन्द्राज ही बदल सकता है। अन्य इन्द्राज अदालत के आदेश के विना बदलने का कोई अधिकार क्वैत्र हासिल नहीं है फिर भी गलत तरीके से प्रतिवादी न0 1 ता 8 के बुजुर्गों से मिल कर ठाकुर जी का नाम हटाकर प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के नाम इन्द्राज कर दिया । रामहेत व बण्डा का नाम दर्ज कर दिया इस इन्द्राज से वादी के हक हकूको पर असर नहीं पडता है इन इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी न0 1 ता 8 वादग्रस्त आराजीयात पर अवैध रूप से बतौर ट्रेस पासर काबिज है। दिनांक 27.4.06 को वादी की ओर से वादी रमेशदास द्वारा प्रतिवादीगण से जमीन खाली कर कब्जा वादी को देने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण हक हकूक खातेदारी वादी से व जमीन पर कब्जा देने से इंकार कर दिया और कहा कि खाता हमारे नाम है तब रेवेन्यू रिकार्ड की नकल लेने पर फर्जकारी का पता चला। प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि इस जमीन को खुर्द बुर्द करेगे और निर्माण करेगे। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात मे बने कुअे को नष्ट कर दिया है तथा बबूल के पेडो को काट दिया है। इसलिए वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि जमीन को खुर्द बुर्द नहीं करे ना ही किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण 2 ता 14 के वारिसान की और से यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।


अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी कतई आर्वीट्रेटरी कपियसली विधि के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी साक्ष्य पीडब्लू 1 रमेशदास के बयान पर भरोसा करने मे गंभीर त्रुटि की है निर्णय व डिकी निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि गवाह पीडब्लू 1 के मुख्य बयान शपथ पत्र मे लिखा गया है कि किसी तथ्य के बारे मे जानकारी नहीं है। साक्ष्य ने


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपने अभिवचनो का भी समर्थन न किया है। बल्कि पेशकर्ता दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2012, प्रदर्श 2 गिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 3 जमाबंदी सेटलमेंट व प्रदर्श 4 जमाबंदी सवंत 2061 से 64 के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होना जाहिर किया है। विधि सलाहकार द्वारा शपथ पत्र तैयार करना बताया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को वहक रेस्पों न० 1 निर्णय करने में विधि की गंभीर भूल की है। निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। रेस्पों संख्या 1 द्वारा वाद पत्र में दिये गये अभिवचनो का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया वह अपनी साक्ष्य में विवादित भूमि व अन्य भूमियो को मंदिर की जागीर की भूमि बताता है जिसमें से कुछ जमीन को मंदिर की खुदकाशत बताता है शेष जमीनो को कौन कौन काशत करता है पता नहीं है। सवंत 2012 में विवादित जमीन पर अपीलांट के आविज होने का तथ्य स्वीकार करता है ऐसी अवस्था में रेस्पों न० 1 को खुदकाशत भूमि न होने से टीनेन्ट को हेरिटेबल खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जावेगे और वह भूमि टीनेन्ट के खातेदारी समझी जावेगी। इस बाबत माननीय राजस्व मंडल द्वारा स्पष्ट सर्कुलर जारी भी किया गया है और सभी अधिनस्थ न्यायालय एवं राजस्व अधिकारियो को उक्त सर्कुलर की पालना के निर्देश दिये है। इस प्रकरण में जागीर ऑफ रिजम्पशन एक्ट के प्रभाव में आने के दिवस अपीलांट के पूर्वज कृषक की हैसियत से काशत करते चले आ रहे थे और मंदिर की खुदकाशत ना होने के सबब अपीलांट कानूनन खातेदार होते हुए विधि के सुव्यवस्थित सिद्धान्त को नजर अंदाज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने कतई मनमाने तरीके से तनकी संख्या 1 ता 3 को वादी/रेस्पों मंदिर के पक्ष में निर्णय कर विधि विरुद्ध डिक्री पारित करके विधि की गंभीर त्रुटि की है। इसलिए डिक्री व निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 की पूर्ण रूप से विवेचना नहीं की ना ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर गौर किया गया। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था जिसे वादी अपनी साक्ष्य से साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है व तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार अपीलांटगण पर था। जिसे अपीलांटगण द्वारा पूर्ण रूप से साबित किया है। रेस्पों न० 1 ने अपनी साक्ष्य जिरह में सवंत 2012 में अपीलांटगण का बतौर कृषक काशत करना व रेस्पों संख्या 2 से 20 वर्ष पूर्व जमीन को छीन लेने का कथन स्वीकार किया है। रेस्पों न० 1 द्वारा विवादित आराजी को अपने वाद पत्र में रेस्पों संख्या 1 की खुदकाशत की होना अभिवचन करते हुए समस्त अनुतोष चाहे है और अपीलांट द्वारा अपने जबाब में इस तथ्य को इंकार किया गया है कि विवादित आराजी सेटलमेंट के वक्त रेस्पों की खुदकाशत की रही थी इस प्रकार रेस्पों न० 1 को यह सिद्ध करना कि विवादित आराजी रेस्पों न० 1 की खुदकाशत की रही है और उक्त तथ्य को रेस्पों न० 1 द्वारा सिद्ध नहीं करने पर वादी का कोई केस नहीं रह जाता है। रेस्पों न० 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजो को अपनी मौखिक साक्ष्य से साबित करने से व अपनी मौखिक साक्ष्य में अपीलांटगण का सवंत 2012 से पूर्व से कब्जा स्वीकृत करने रेस्पों न० 1 द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी अपीलांटगण की खातेदारी में दर्ज होना सिद्ध है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी तथ्य की स्वीकारोक्ति से अच्छी कोई साक्ष्य नहीं हो सकती फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 का विनिश्चय पूर्णतः विधि विरुद्ध है। तनकी संख्या 2 रेस्पों न० 1


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

साक्ष्य से ही अपीलांटगण के पक्ष में साबित है इस कारण निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध है और अपास्त किये जाने योग्य है। स्थाई निषेधाज्ञा व दखल बाबत कोई तनकी न्यायालय द्वारा विचरीत नहीं की है। रेस्पों 0 नं 1 द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी नं 1 रामखिलाडी रेस्पों 0 नं 2 से 20 वर्ष पूर्व कब्जा छीनने का कथन अपनी जिरह में किया है यानि रेस्पों 0 नं 1 को अपीलांटगण की साधिका खातेदारी काशतकारी का ज्ञान दायरी दावा से बीसियों वर्ष पूर्व से रहा है यानि रेस्पों 0 नं 1 को कब्जा वापसी की भी मियाद निकल चुकी है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वगैर स्थाई निषेधाज्ञा की तनकी कायम किये दखल व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष रेस्पों 0 नं 1 को प्रदान करते हुए निर्णय व डिक्री पारित करने में विधि की भारी त्रुटि की है। इसलिए निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। रमेशदास द्वारा अपने आपको बाबा तुलसीदास का चेला होना व बचपन में गोद लेने का कथन किया है व अपने आपको मंदिर का पुजारी होना बताया है व विवादित भूमि का मंदिर के स्थान पर अपीलांटगण के नाम होने की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिये जाना बताया है। रेस्पों 0 नं 1 के वाद पत्र के अभिवचन व साक्ष्य विरोधाभासी है। अपीलांटगण साक्ष्य डी डब्लू 1 से रमेशदास का मंदिर की सेवा पुजा करना उसका चैनपुर में रिहायश करना व रमेशदास को दावा करने का अधिकार नहीं होना पूर्ण रूप से साबित होने पर रेस्पों 0 नं 1 द्वारा उक्त साक्ष्य का खण्डन नहीं करने पर एवं रेस्पों 0 नं 1 की जानकारी में अपीलांटगण का साधिका कब्जा काशत खातेदारी बीसियों वर्ष पूर्व स्वीकृत करने पर वाद कारण दिनांक 27.4.06 का बनावटी होने पर भी वाद पत्र में आई साक्ष्य का सही विवेचन ना कर वाद पत्र रेस्पों 0 नं 1 बहस रेस्पों 0 नं 1 निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी वकील द्वारा अपीलांटगण को समय पर नहीं दी गई उसके द्वारा प्रत्येक पेशी पर आने के लिए मनाही कर दिया गया था उसके पश्चात कोविड 19 के कारण सभी अदालतों में कार्य बंद होने एवं लॉकडाउन होने के कारण निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। दिनांक 30.7.21 को न्यायालय में आने पर निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होने पर नकल निर्णय व डिक्री की प्राप्त की जाकर अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश की गई है। इसलिए अपील पेश करने में हुए डिले को कण्डौन किया जावे। रेस्पों 0 नं 2 का विवादित जमीन से किसी प्रकार का कोई हक व कब्जा नहीं है ना ही रेस्पों 0 नं 2 द्वारा कभी काशत किया है संपूर्ण भूमि हम अपीलांटगण के कब्जे काशत खातेदारी में है और सारे हक हकूक विवादित जमीन बाबत अपीलांटगण में निहित हो चुके हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रेस्पों 0 नं 2 के नाम पेपर एन्ट्री के आधार पर वादी रेस्पों 0 नं 1 द्वारा रेस्पों 0 नं 2 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जो बाबजूद तामिल उपस्थित नहीं हुआ है। रेस्पों 0 नं 2 के सारे हक हकूक अपीलांटगण में निहित होने से रेस्पों 0 नं 2 इन्ट्रेस्ट नहीं है इसलिए उसको रेस्पों 0 बनाया गया है। विवादित भूमि के सम्पूर्ण रकबे की अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि के सम्पूर्ण रकबे को अपीलांटगण के रकबे में शुमार किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पोंड के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से तनकी संख्या 1 व 2 को वादी/रेस्पोंड के हक में निर्णित किया गया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से 'दावा' एवं जबाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई है। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी/रेस्पोंड को दिया गया था जिसे वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से साबित किया है इसी प्रकार तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण पर था जिसे अपीलान्ट/प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात का निर्णय विधिवत रूप से वादी/रेस्पोंड के पक्ष में किया गया है। वादी मंदिर नाबालिग है। जिसकी भूमि पर प्रतिवादी/अपीलान्ट का कब्जा बतौर ट्रेस पासर अधिनस्थ न्यायालय ने माना है। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के नाम हुए गलत इन्द्राज को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है। सम्वत 2012 में वादग्रस्त आराजी वादी ठाकुरजी की खातेदारी में रही है जो प्रदर्श 1 से साबित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से सम्वत 2015 में वादी के नाम के खातेदारी के कॉलम से खातेदारी इन्द्राज हटा दिये गये। जिसका सेटलमेंट को कोई अधिकार हासिल नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का सम्पूर्ण रूप से विधिक अवलोकन कर एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा नं० 202, 203, 204 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 5 बीघा ग्राम सौरया पटवार हल्का खूबनगर की खातेदारी सम्वत 2012 में वादी मंदिर के नाम रही है जो प्रदर्श 1 से स्पष्ट साबित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजीयात की खातेदारी के कॉलम में से हटा जाकर प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण के बुजुर्गान के नाम दर्ज किया गया है। जिसका सेटलमेंट को कोई अधिकार हासिल नहीं है। जहाँ तक वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे का प्रश्न है तो प्रतिवादीगण/अपीलान्ट बतौर ट्रेस पासर ही काबिज है। अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजीयात उनकी पुश्तैनी खातेदारी होने के तथ्य को स्पष्ट कर सकें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को दिया गया था जिसे प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण साबित करने में असफल रहे हैं जबकि वादीगण/रेस्पोंड द्वारा अपने आप को पुजारी होना अपनी मौखिक साक्ष्य से साबित किया गया है। अपीलान्ट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दखल व स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में कोई तनकीयात कायम नहीं की है, इस संबंध में स्पष्ट है कि जब वादी का वाद पत्र तनकीयात से पूर्णतया साबित होता है तो विधि के सिद्धान्तों अनुसार प्रतिवादीगण दखल व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। वादी मंदिर शास्वत नाबालिग है जिसकी भूमि को किसी को भी खुर्द बुर्द



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को बतौर पुजारी होने से दावा दायर करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीवार विवेचन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य का विवेचन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांत की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 58/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.3.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्थान अपीलाधिकारी
सवाई माधोपुर